समाचार संक्षेप

सिंधी समाज आर्थिक रुप से कमजोर सिंधी परिवारों का कराएगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। भोपाल की सिंधी सेंट्रल पंचायत में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला किया है। पंचायत कमेटी की सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बीमा कंपनियों से बातचीत चल रही है। जो बीमा कंपनी कम प्रीमियम पर पॉलिसी जारी करेगी उस बीमा कंपनी से प्रथम चरण में 10000 परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कराने का लक्ष्य समाज ने तैयार किया है। समाज ने जिन सिंधी परिवारों की आय 2 लाख वार्षिक से कम है। उन्हें इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। सिंधी समाज 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक रूप से कमजोर सिंधी परिवारों का बीमा कराएगा।

सामान्य से ज्यादा बारिश हुई तो डूबेगा शहर

भोपाल, 16 जुलाई (सन्यूस)। राजधानी में अगर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई तो शहर का करीब 30 फीसदी हिस्सा पानी में डूब सकता है। शहर के 75 फीसदी हिस्से में बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। जिसके कारण जल भराव की स्थिति बनती है। यह खुलासा ग्रीन ब्लू मास्टर प्लान की रिपोर्ट में किया गया है। शहर से बारिश के पानी की प्रॉपर निकासी के लिए 1620 किमी का ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है, लेकिन इसके बदले सिर्फ451 किमी ही ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है। बाकी 30 किमी प्राकृतिक नाली से पानी खुद बह जाता है। सूत्रों की माने तो शहर में नगर निगम, सीपीए, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड आदि एजेंसियां सड़क बनाती हैं लेकिन सड़क के साथ पानी निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान नहीं जाता। 90 फीसदी सड़कों में यही समस्या है। जिसके कारण एक तो जलभराव की समस्या हो रही है, वहीं सड़कें समय से पहले ही उखड़ जाती हैं। वर्तमान में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड बीएससीडीसीएल की प्रस्तावित स्मार्ट रोड और बुलेवार्ड स्ट्रीट में ड्रेनेज का प्रावधान किया गया है। बाकी सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। ग्रीन ब्लू मास्टर प्लान की मानें तो शहर की नालियों में बारिश के पानी के साथ ही 80 फीसदी सीवेज मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि बारिश के दौरान गंदा पानी ही सड़क और घरों में भरता है। जो बीमारी का कारण बनता है।

जनसंघ एक बार पुनः चुनाव मैदान में

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। यह पार्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी प्रथम चरण में 50 50 उम्मीदवार तीनों राज्यों से चुनाव मैदान में उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी से नाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी समीर सिंह चंदेल तीनों राज्यों में पार्टी संगठन को खड़ा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है, जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉ बलराज मधोक के साथ मिलकर दिल्ली में की थी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। इसमें जनसंघ का विलय करने के लिए बलराज मधोक तैयार नहीं हुए। जिसके कारण यह पार्टी अलग.थलग होकर रह गई थी।संघ ने इस समय के नाम से नई पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भारत भूषण पांडे का कहना है, कि भाजपा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राजनीति तो कर रही है। किंतु उनकी नीतियों का पालन नहीं कर रही ।है भारतीय जनता पार्टी ने दोहरे मापदंड अपना लिए हैं। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लाखों स्वयंसेवकों और प्रचारक भी भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से खुश नहीं है। जिसके कारण अब जनसंघ चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है।इसमें संघ और भाजपा के कार्यकर्ता भी जुड़ रहे है।

तीन नये मेडिकल कॉलेज में 400 सीट बढ़ने की संभावना

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नीट यूजी. 2018 के प्रथम चरण की काउंसलिंग से प्रवेशित सभी अभ्यर्थीयों को सूचित किया जा रहा है, कि प्रदेश के तीन नये मेडिकल कॉलेज में 400 अतिरिक्त सीटों के बढ़ने की संभावना है। इन 400 सीटों को द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रथम चरण के प्रवेश के समय और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के समय बेहतर विकल्प का लाभ ले सकते हैं। केवल एक बार संशोधन करने के लिये अभ्यर्थी के लॉगिन प्रोफाईल पर एडिट अपग्रेड का लिंक दिया जा रहा हैं। यह सुविधा 16 जुलाई से शाम 5 बजे से 21 जुलाई शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो अपने द्वारा प्रथम चरण में प्रवेश के लिये दिये गये बेहतर विकल्प का लाभ लेने में कोई संशोधन नहीं करना चाहते है, तो उनके प्रथम चरण के प्रवेश के समय दिये गये बेहतर विकल्प को ही द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिये मान्य माना जाएगा। काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया जानकारी वेबसाइट और निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध है। संचालक, चिकित्सा शिक्षा ने बताया है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित सूचना के लिये संचालनालय की वेबसाइट और एमपी ऑनलाइन पोर्टल के सम्पर्क में रहें।

96 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक भी छात्र ने नहीं लिया एडमिशन

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की इस साल बड़ी दयनीय हालत है। प्रथम राउंड की काउंसलिंग में केवल 5807 छात्रों ने शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है 96 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। छात्र छात्राओं का इंजीनियरिंग की शिक्षा से मोह अब पूरी तरह खत्म हो चला है। इंजीनियरिंग कर चुके लोगों को 2 लाख वार्षिक का भी पैकेज नहीं मिल पाने के कारण इस साल इंजीनियरिंग के प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 160 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 61000 सीटें स्वीकृत हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण की जो काउंसलिंग के लिए आवेदन मंगाए थे। उसमें 15634 छात्रों ने आवेदन किए थे। किंतु इसमें प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मात्र 5807 प्रथम राउंड में रही है। इसमें शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1368 छात्र.छात्राओं ने प्रवेश लिया है वही निजी कॉलेजों में 4100 छात्र.छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया है

प्रथम चरण की काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा 1840 प्रवेश हुए हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 816 छात्र.छात्राओं ने प्रवेश लिया है सिविल ब्रांच में 653 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 614 आईटी ब्राँच में 279 और इलेक्ट्रिकल में 273 छात्र.छात्राओं ने प्रवेश लिया है। इंजीनियरिंग की तीन ब्रांच ऐसी भी हैं। जिसमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6200 सीटें हैं। इसमें प्रथम चरण में मात्र 1368 एडमिशन हुए हैं। 20 जुलाई को दूसरी बार अपग्रेडेशन का काम होगा। इसमें और कितने प्रवेश होते हैंए या कितने लोग अपनी पसंद को बदलते हैं। यह 20 जुलाई को पता लगेगा। वर्तमान स्थिति में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश अब आसान हो गया है। पिछले 5 वर्षों से इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग की सीटें घटती चली आ रही हैं। हर साल छात्र कम होते जा रहे हैं। 96 इंजीनियरिंग कॉलेजों में किसी भी ब्रांच में एक भी प्रवेश नहीं होने के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने के अलावा और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। 2000 के बाद जिस तरीके से इंजीनियरिंग की मांग छात्र छात्राओं के बीच बढ़ी थी। वह अब समाप्त हो गई है। सही मायने में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मैं जो स्वीकृत सीट है। उनके अलावा निजी इंजीनिरिंग कॉलेजों की जरूरत भी नहीं रह गई।

विस अध्यक्ष के परिवार का सरकारी भूमि पर कब्जा

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉण् सीतासरन शर्मा के परिवार का होशंगाबाद की एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। जमीन पर स्कूल संचालित किया जा रहा है और अवैध रूप से दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गई हैं। यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल ने। श्री अग्रवाल का कहना है कि सालों पुराने इस अतिक्रमण को दिग्विजय सरकार के समय भी अफसरों ने दबा दिया था। अग्रवाल ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। श्री अग्रवाल ने कल यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि इस मामले का खुलासा 29 जनवरी 2003 को हुआ था। तब तत्कालीन कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में एक लाख 88 हजार 100 वर्गफीट के रकबे की नजूल जमीन को खेल का मैदान बताया था।

उन्होंने मुख्यमंत्री के तत्कालीन सचिव को जमीन नजूल की बताने संबंधी राजस्व रिकॉर्ड भी रिपोर्ट में दिया था। जमीन एसएनजी स्कूल से लगी होने के कारण इसे एसएनजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। स्कूल चलाने वाली नर्मदा शिक्षा समिति को स्टेडियम निर्माण के लिए काम करने वाली एजेंसी ने बनाया था और समिति के पदेन अध्यक्ष होशंगाबाद कलेक्टर रहते हैं। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष डॉण् सीतासरन शर्मा ने कहा कि पहले सरकारी रिकॉर्ड देख लें फिर कांग्रेस नेता आरोप लगाए। कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। 1946. 47 में नर्मदा शिक्षा समिति की जमीन थी, जिसे रजिस्टर्ड डाक्यूमेंट से 1956.57 में हमने ली थी।

नर्मदा एजुकेशन सोसायटी को लेकर कांग्रेस परेशान- कोठारी

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि नर्मदा एजुकेशन सोसायटी होशंगाबाद के संबंध में कतिपय समाचार.पत्रों में कांग्रेस के प्रवक्ता मानक अग्रवाल द्वारा बिना तथ्यों के असत्य एवं भ्रामक आरोप लगाए गए हैंए जो निराधार हैं। कांग्रेस मध्यप्रदेश में जनाधार के संकट से जूझ रही है। इसलिए असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्मदा एजुकेशन सोसायटी जिला कलेक्टर होशंगाबाद के नियंत्रण में शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करती थी। सोसायटी का अनेक वर्षों से इस जमीन पर विधिवत मालिकाना हक है। नर्मदा एजुकेशन सोसायटी का पंजीयन वर्ष 1946.47 में किया गया। वर्ष 1957.58 में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि एवं भवन क्रय किए गए तब से उक्त भूमि नर्मदा एजुकेशन सोसायटी के अधिपत्य में चली आ रही है। सन् 1972 में एसएनजी् स्कूल एवं नर्मदा महाविद्यालय के शासनाधीन होने के बाद से न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं। असत्य शिकायतों की जांच भी हुई जिससे स्थिति स्पष्ट भी हो चुकी है कि इस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। कोठारी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है आसपास के गांवों के बच्चे जो कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे शिक्षा से वंचित हो जाये। कांग्रेस के यह मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था गाँव में ही उपलब्ध होगी- डॉ. मिश्र

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉण् नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया जिले के ग्राम चिरूला में हायर सेकेण्डरी स्कूल के उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अब गाँव के बच्चों को हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा गाँव में ही उपलब्ध हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का निरंतर विकास किया जा रहा है। बच्चों के लिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था गाँव में ही उपलब्ध होगी।

मंत्री डॉण् मिश्र ने कहा कि चिरूला रेल्वे स्टेशन पर क्रासिंग की परेशानी को देखते हुए अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है। गाँव में नल.जल योजना से स्वच्छ पानी प्रदाय किया जा रहा है। डॉ. मिश्र ने ग्रामीणों की मांग पर सिंचाई के लिए 3.90 करोड़ रुपए लागत की नहर बनाने की घोषणा की।

सुल्तानिया अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। राजधानी के सुल्तानिया अस्पताल ;लेडी हास्पिटलद्ध में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहां जितनी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं, उसके हिसाब से सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। मरीजों को भर्ती कराने के लिए आबिदा वार्ड के पीछे गैलरी में दो कतार में पलंग बिछाए गए हैं। इसमें एक पलंग में छत से पानी टपकता रहा है। पलंग के नीचे भी पानी फैला है। मरीजों के परिजन यहां से संभलकर निकल रहे हैं। पलंग दीवार से सटे होने की वजह से चीटियां बिस्तरों पर चढ़कर प्रसूताओं व उनके नवजातों को काट रही हैं। प्रसूताएं उमस से बेहाल हो रही हैं। इस तरह की कई अव्यवस्थाओं से मरीजों को व उनके परिजनों को दो.चार होना पड़ रहा है। 185 बेड का अस्पताल है, लेकिन यहां पर हर समय 250 से ज्यादा महिलाएं भर्ती रहती हैं। अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाने की जगह नहीं है। लिहाजा एक बेड पर दो.दो प्रसूताओं को भर्ती किया जाता है। उनके नवजात बच्चे व परिजन भी उन्हीं बिस्तर पर रहते हैं। इस वजह से मरीजों व नवजातों को एक दूसरे से संक्रमण का खतरा रहता है। एमसीआई के मापदंडों के अनुसार दो बेड के बीच 3 फीट का अंतर होना चाहिए। बिजली गुल होने से ऑपरेशन थियेटर तक में अंधेरा छा जा जाता है। अस्पताल में जनरेटर लगा है, पर ऑटोचेंजर नहीं होने से बिजली गुल होने के बार जनरेटर अपने आप चालू नहीं होता। ऐसे में 15.20 मिनट लग जाते हैं। जनरेटर देर तक चलने के बाद उसे ठंडा करने के लिए बंद करना पड़ता है। इस दौरान गंभीर मरीजों के लिए लगे मल्टी पैरा मॉनीटर तक बंद हो जाते हैं।

सुल्तानिया अस्पताल के ठीक सामने महज 100 मीटर की दूरी पर शाहजहांनी पार्क है। यहां हर दिन कोई न कोई धरना चलता है। धरने में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। इससे नवजातों की सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। अस्पताल अधीक्षक डॉण् अजय शर्मा ने करीब छह महीने पहले प्रदर्शन बंद कराने के लिए पुलिस को पत्र लिखा था। अब उन्होंने दोबारा पत्र भेजा है। अस्पताल में मरीजों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। परिजन बाहर लगी टंकी से पानी भरकर लाते हैं। यहां पर भी परिजन बर्तन भी धोते हैं, जिससे गंदगी रहती है। टंकी के आसपास सफाई भी नहीं की जाती। बच्चा पैदा होने के बाद उसकी हालत गंभीर हुई तो फौरन सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में भर्ती करना पड़ता है। प्रसव कक्ष व एसएनसीयू आपस में जुड़े होने चाहिए।

सुल्तानिया से हमीदिया के बीच देरी करीब डेढ़ किमी है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से नवजातों को शिफ्ट करने में एक घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे में नवजात की हालत और बिगड़ जाती है। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन होने के बाद भी प्रसूताओं की सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। प्रसव के पहले गंभीर स्थिति में भी इस जांच के लिए प्रसूताओं को हमीदिया अस्पताल भेजा जाता है। हमीदिया अस्पताल से कोई भी रेडियोलॉजिस्ट सुल्तानिया में जांच करने को तैयार नहीं है। इस बारे में सुल्तानिया अस्पताल अधीक्षक डॉण् अजय शर्मा का कहना है कि जगह कम होने के चलते गैलरी में बेड लगाए गए हैं। खाने की चीजें बिस्तर में गिरने से चीटियां आ जाती हैं। अस्पताल में चूहे व कीटों को मारने के लिए दवाएं डाली जाती हैं।

जेपी सहित 20 अस्पतालों में बनेंगे माड्यूलर ओटी

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। शहर के जेपी जिला अस्पताल में माड्यूलर ऑपरेशन थियेटर ;ओटीद्धबनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 20 जिला अस्पतालों में माड्यूलर ऑपरेशन थियेटर ;ओटीद्धबनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 300 बिस्तर से ज्यादा वाले जिला अस्पतालों में ओटी बनाए जाएंगे । इस तरह की ओटी बनने से मरीजों में संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन थियेटर बढ़ने से मरीजों को सर्जरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओटी बनाने के लिए अक्टूबर के पहले टेंडर जारी हो जाएंगे। माड्यूलर ओटी बनने से जिला अस्पतालों में बड़ी सर्जरी भी हो सकेंगी। साधारण ओटी में बड़ी सर्जरी से संक्रमण को जोखिम रहता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ;एनएचएमद्ध के अफसरों ने बताया कि 20 जिलों में माड्यूलर ओटी बनाए जाने हैं। इनमें 10 जिलों के लिए राशि ट्राइबल विभाग से मिल रही है। 10 जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ओटी बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में कुछ जगह दो और जगह तीन ऑपरेशन थियेटर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है।

मालूम हो कि जेपी अस्पताल में अभी तीन ओटी है। मुख्य ओटी माड्यूलर है। नाकए कान एवं गला विभाग व गायनी विभाग के साधारण ओटी हैं। माड्यूलर ओटी में वह सब व्यवस्थाएं नहीं हैं जो आधुनिक माड्यूलर ओटी में होनी चाहिए।ओटी में पहुंचने के पहले तीन जोन होते हैंए पर ऐसा नहीं है। कायाकल्प अवार्ड के लिए एनएचएम की टीम ने पिछले साल जेपी अस्पताल के ओटी का निरीक्षण किया तो ओटी टेबल पर धूल मिली थी। फर्श को कीटाणु रहित करने के लिए सही केमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रदेश के 13 जिलों में सुपर स्पेशलिटी सर्जरी के लिए चुना गया है। इसमें जेपी अस्पताल भी है। इस अस्पताल के अलावाए मेडिकल कॉलेज या निजी डॉक्टरों से सुपर स्पेशलिटी सर्जरी के लिए अनुबंध किया जाएगा। यहां गाल ब्लेडरए बच्चेदानी निकालनेए पथरी की दूरबीन तकनीक से सर्जरी की जाएगी। इस तरह की सर्जरी माड्यूलर ओटी में होने से मरीजों को किसी तरह के संक्रमण का डर नहीं रहेगा। दूसरा फायदा यह कि मुख्य ओटी में बैक्टीरिया या फंगस मिलने पर दो दिन के लिए बंद करना पड़ता है। इस दौरान ऑपरेशन टालना पड़ता है। अब दो और ओटी बढ़ने से यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। ओटी में हेपा फिल्टर लगा होता है जो बैक्टीरिया व वायरस को फिल्टर कर देता है। वे अंदर नहीं आ पातेए जिससे संक्रमण का डर नहीं रहता। ओटी का प्रोटोकाल होता है। ह्यूमिडिटी ;आर्द्रताद्ध कंट्रोल रहती है। ऐसा इसलिए की नमी का स्तर मापदंड से कम ज्यादा होने पर बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है। ओटी में हर घंटे में 15.20 बार एयर चैंजेज होते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट लगे होते हैं जो एयर को मापदंड के अनुसार रखते हैं।

रेलवे ने टिकट कैंसिल कर कमाए 41 करोड रुपए

भोपाल, 16 जुलाई (सन्यूस)। रेलवे को वर्ष 2016.17 में टिकट कैंसिल करने से मात्र एक जबलपुर जोन से 41 करोड रुपए की कमाई हुई हैए जबकि एक साल पहले यह 36 करोड़ रुपए थी। औसतन भारतीय रेलवे को हर घंटे कैंसिल टिकट से 16 लाख रुपए की आय होती है। वहीं एक दिन में औसतन करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए रेलवे कमाती है। सामान्य उपभोक्ता के लिए रेलवे का टिकट कैंसिल कराने पर कटने वाली कुछ राशि का भले ही बहुत महत्व न होए लेकिन रेलवे के लिए देशभर में कैंसिल होने वाले ऐसे टिकट बड़ी आय का साधन हैं। रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि वेटिंग टिकट के कैंसिल होने और अन्य कारणों से रद्द होने वाली टिकटों पर 2016.17 में रेलवे ने लगभग 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। कैंसिल टिकट से होने वाली रेलवे की कमाई साल दर साल बढ़ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव खरे ने इसे लेकर भारतीय रेलवे से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। रेलवे ने बताया है कि 2015.16 में कैंसिल टिकट से 1104 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई थी। वहीं 2016.17 में यह बढ़कर 1386 करोड़ रुपए हो गई। भारतीय रेलवे ने 2016.17 में एक लाख 64 हजार करोड़ रुपए का राजस्व कमाया था।

सामाजिक कार्यकर्ता राजीव खरे ने आरोप लगाया कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेता है और चार्ट तैयार होने पर उसका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता तो रेलवे वेटिंग टिकट कैंसिल करने का भी पैसा लेता है। जबकि इसमें पैसेंजर की कोई गलती नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब पैसेंजर खुद टिकट कैंसिल करवाएए तभी यह चार्ज वसूला जाना चाहिए। इसे लेकर राजीव खरे जल्द ही कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल करने वाले हैंए ताकि रेलवे के आम यात्रियों को इस खुली लूट से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे को यात्रियों के हित में भी फैसला लेना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रह है।

आधार मान्य नहीं करने वाले आरटीओ पर होगी कार्रवाई

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ द्वारा आधार मान्य नहीं किया गया तो उसके खिलाफकार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शासन ने परिवहन आयुक्त को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के साथ आईडी प्रूफके रूप में आधार कार्ड स्वीकार नहीं करने पर जिला परिवहन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आईडी के रूप में आधार कार्ड मान्य किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर आधार कार्ड को आईडी प्रूफ के रूप में मान्य कर चुका है। 20 मार्च 2018 को राजपत्र भी प्रकाशित हो चुका हैए लेकिन प्रदेश में जिला परिवहन अधिकारी ;आरटीओद्ध अब तक इसे मान्य नहीं कर रहे थे। बार.बार ऐसी शिकायतें आने के बाद राज्य शासन ने परिवहन आयुक्त को केंद्र सरकार के राजपत्र का पालन कराने को कहा है। शासन में बैठे अफसरों का कहना है कि 10 दिन में यह आदेश सभी आरटीओ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद शिकायत आती है तो संबंधित आरटीओ के खिलाफकार्रवाई भी की जाएगी।

मालूम हो कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मतदाता परिचत्र पत्रए जीवन बीमा पॉलिसीए पासपोर्टए स्कूल प्रमाण पत्र ;अंकसूचीद्धए जन्म प्रमाण पत्रए सरकारी कर्मचारियों के मामले में वेतन पर्ची और शपथ पत्र मांगा जाता है। यह सभी दस्तावेज एड्रेस प्रूफ और जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मांगे जा रहे हैं। जबकि आईडी प्रूफ के लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता डॉण् प्रकाश अग्रवाल ने उठाया था। उनकी दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग के उप सचिव कमल नागर का कहना है कि इस मामले में अलग से राजपत्र जारी करने की जरूरत नहीं है। राज्य शासन ने परिवहन आयुक्त को राजपत्र का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

जनता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत- मुख्यमंत्री

भोपाल, 16 जुलाई (ए)। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस सत्ता में रही तब प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया। कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ नाइंसाफी की है। कांग्रेस ने प्रदेश का बंटाढार किया, मैंने इतिहास बदल दिया है। प्रदेश को विकासशील बनाया है। अगले 5 सालों में समृद्ध राज्य बनाएंगे। हमने असंभव को संभव किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज बड़नगर में जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कही।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग-नारायणपुर

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

क्रमांक/618/निविदा/व.ले.लि./ग्रा.यां.सेवा/2018-19 नारायणपुर दिनांक 11/07/2018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती हैः-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये लाख में)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
1	हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य जम्हरी विकास खण्ड नारायणपुर	23.53 लाख	25.07.2018 (शाम 5.00 बजे तक)

2. उक्त निर्माण कार्यों की निविदा सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं जानकारी **दिनांक 13.07.2018** से विभागीय वेबसाईट http://cg.nic.in/resworks से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
नारायणपुर

जी-53543